करेंट अफेयर्स

बिहार

अक्तूबर

(संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार **3**

- नीति आयोग की तर्ज़ पर रैंकिंग 3
- बिहार में बेरोज़गारी की स्थिति 3
- नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य 4
- बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंज़ूरी 4
- सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला बना पूर्णिया 4
- गांगेय डॉल्फिन की गणना 5
- ‘गंगाजल उद्वह योजना’ 5
- पटना उच्च न्यायालय में दो नए जजों की नियुक्ति 5
- प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट 6
- बिहार देश का पहला राज्य, जहाँ सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर 6
- अमित खरे 6
- बिहार में डायरिया का प्रकोप 7
- बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह 7
- विपश्यना ध्यान 8
- कृषि यंत्र बैंक 8
- मनरेगा कार्यों में महिलाओं की 54 प्रतिशत हिस्सेदारी 9

दृष्टि The Vision

नोट :

बिहार

नीति आयोग की तर्ज़ पर रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की तर्ज़ पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पूरे प्रदेश में ज़िलेवार रैंकिंग करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- यह रैंकिंग सतत् विकास लक्ष्य के लिये निर्धारित 17 प्रमुख मानकों के क्रियान्वयन पर राज्य के ज़िलों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए जारी की जाएगी।
- इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुवहानी ने राज्य के सभी ज़िलाधिकारियों को पत्र लिखकर लक्ष्य को लेकर ज़िला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है।
- इसमें यह अवलोकन किया जाएगा कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत् विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों पर ज़िले की क्या उपलब्धि रही है।
- ज़िला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य का मूल्यांकन के लिये ज़िला योजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी (मॉनीटरिंग) की ज़िम्मेदारी ज़िलाधिकारी को दी गई है।
- उललेखनीय है कि सतत् विकास के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 17 सतत् विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। यह ब्वर्ष 2016-30 के लिये वैश्विक एजेंडा है, जो 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था।

बिहार में बेरोज़गारी की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

- 1 अक्टूबर, 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी के द्वारा जारी किये गए आँकड़े में यह खुलासा हुआ है कि बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोज़गारी में 3.6 प्रतिशत की कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों से स्पष्ट है कि जहाँ अगस्त माह में बेरोज़गारी 13.6 प्रतिशत थी, वहीं सितंबर माह के अंत तक घटकर 10 प्रतिशत हो गई है।
- यद्यपि बिहार में बेरोज़गारी अब भी राष्ट्रीय औसत 6.9 प्रतिशत से ज़्यादा है, जो एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है।
- आँकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि बिहार में गाँवों की तुलना में शहरों में बेरोज़गारी अधिक है।
- ग्रामीण बेरोज़गारी घटकर जहाँ नौ प्रतिशत के स्तर पर आ गई है, वहीं शहरी बेरोज़गारी अभी भी 16.9 प्रतिशत है।
- बिहार में पिछले तीन माह की बेरोज़गारी से संबंधित आँकड़े नीचे चार्ट में दिये गए हैं&

आंकड़े प्रतिशत में

	जुलाई	अगस्त	सितंबर
कुल बेरोज़गारी	13	13.6	10
शहरी बेरोज़गारी	17.5	19.5	16.9
ग्रामीण बेरोज़गारी	12.4	12.8	09

नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नीति आयोग के द्वारा देश भर के ज़िला अस्पतालों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें बिहार की स्थिति को सबसे दयनीय बताया गया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में स्पष्ट है कि बिहार के ज़िला अस्पतालों में बेडों की संख्या देश भर में सबसे न्यूनतम है, जो प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 6 बेड हैं।
- ध्यातव्य है कि रिपोर्ट में प्रति लाख आबादी पर बेडों का राष्ट्रीय औसत 22 है तथा बेडों की उपलब्धता के मामले में शीर्ष पर दिल्ली (59 बेड) तथा कर्नाटक (33 बेड) हैं, वहीं निम्न स्थान पर बिहार (6 बेड) एवं झारखंड (9 बेड) हैं।
- बिहार के औसतन 8 अस्पतालों में ही डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस की सुविधा उपलब्ध है।
- बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर क्रियाशील बेडों की संख्या के मामले में सदर अस्पताल, सहरसा शीर्ष पर है।

बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबे में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय (Directorate of Backward and Most Backward Classes) के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- निदेशालय के गठन में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने में आसानी होगी तथा योजनाओं की अच्छी तरह से निगरानी भी की जा सकेगी।
- ध्यातव्य है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिये कल्याण विभाग से अलग कर राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन किया गया था।
- विभाग ने निदेशालय के संचालन के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों के 446 पदों को भी मंज़ूरी दी है, जिसमें 26 पद निदेशालय के स्तर के और 420 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये हैं।

सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला बना पूर्णिया

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार का पूर्णिया ज़िला देश का ऐसा प्रथम ज़िला बन गया है, जहाँ की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार की पहल पर ज़िले में 25 जनवरी से किताब दान अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत केनगर प्रखंड की परोरा पंचायत से की गई थी।
- इस अभियान के तहत ज़िले की सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले जा चुके हैं।
- ध्यातव्य है कि इस अभियान के तहत खोले गए पुस्तकालयों का निरीक्षण 29 सितंबर, 2021 को नीति आयोग की एक टीम के द्वारा भी किया गया है।
- इस अभियान से साक्षरता के मामले में पिछड़े इस ज़िले में शिक्षा को बढ़ावा मिलने की आशा है।

गांगेय डॉल्फिन की गणना

चर्चा में क्यों?

- 5 अक्टूबर, 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा गांगेय डॉल्फिन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गांगेय डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य को संपादित करने के लिये डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगाँव तक के करीब 60 किमी. क्षेत्र को 'गंगैटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया है।
- डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी।
- विदित है कि गांगेय डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया था तथा आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

'गंगाजल उद्वह योजना'

चर्चा में क्यों?

- 6 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के द्वारा 'गंगा जल उद्वह योजना' के कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- हथीदह-मोहनाजे-तेतर-अबगिल्ला तक कुल 150 किमी. की पाइपलाइन में से लगभग 118 किमी. पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- विदित हो कि 'गंगा जल उद्वह योजना' बिहार सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय में दो नए जजों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

- 6 अक्तूबर, 2021 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय तथा रजिस्ट्रार विजलेंस सुनील कुमार पंवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिये कुल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश सहित केवल 19 न्यायाधीश ही पदास्थापित थे। दो नए जजों की नियुक्ति से अब यह संख्या 21 हो गई है।
- दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर का पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है, वहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया है।
- पटना उच्च न्यायालय में मुकदमों की बढ़ती संख्या एवं न्यायाधीशों की कमी के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। अब दो नए जजों की नियुक्ति से सुनवाई में थोड़ी शीघ्रता आने की संभावना है।

प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में दवाओं की कालाबाज़ारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिये औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी।
- कैंसर, शूगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी।
- दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इसका कर्त्तव्य होगा।
- इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वाँ राज्य होगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस तरह की यूनिट का गठन किया है।

बिहार देश का पहला राज्य, जहाँ सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

चर्चा में क्यों ?

- 11 अक्टूबर, 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- 1110 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को अगले 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- परियोजना के पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहाँ सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगे होंगे।
- प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन और एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा।
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिये किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियाँ करेंगी।
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में तीन फीसदी छूट दी जाएगी।

अमित खरे

चर्चा में क्यों ?

- 12 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अमित खरे की प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 1985 बैच के बिहार/झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहे अमित खरे इसी वर्ष 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं।
- इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ/योगदान निम्नलिखित हैं-
- बिहार के चारा घोटाला को उजागर करना।
- देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को नया स्वरूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान।

बिहार में डायरिया का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार के औरंगाबाद के बाद पश्चिमी चंपारण ज़िले में डायरिया के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया होने पर व्यक्ति बार-बार उल्टी और दस्त करता है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- डायरिया के लिये विविध प्रकार के जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं, उदाहरण के लिये रोटा वायरस एवं नोरो वायरस।
- डायरिया संक्रमण संदूषित भोजन करने, प्रदूषित जल पीने एवं व्यक्ति से व्यक्ति में गंदगी व अस्वच्छता का परिणाम है।
- डायरिया का स्वच्छ जल पीने, स्वच्छता बनाए रखने एवं ओरल रिहाइड्रेशन आदि के द्वारा उपचार किया जा सकता है।

बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह

चर्चा में क्यों ?

- 21 अक्तूबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के सौ साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसके पहले राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- 25 फीट ऊँचे इस स्मृति स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के सौ वर्ष पूरे होने की याद में की जा रही है। विधानसभा का यह भवन 1920 के मार्च महीने में बनकर तैयार हुआ था।
- बिहार और उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिलने के बाद 7 फरवरी, 1921 को विधानसभा के नव-निर्मित भवन में पहली बैठक हुई थी। वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है।
- 7 फरवरी, 1921 को हुई पहली बैठक में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर भाग लिया था। अंग्रेज़ों के समय यह भवन बिहार-उड़ीसा विधानपरिषद के नाम से जाना जाता था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के आने के बाद बिहार और उड़ीसा को संपूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त हुआ। बिहार के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे।
- आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव के बाद 1952 में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई, तब विधानसभा में 331 सदस्य थे। वर्तमान बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं।
- इतालवी पुनर्जागरण शैली में बिहार विधानसभा के इस भवन का निर्माण हुआ है। इसमें समानुपाति संतुलन दिखता है। लंबे-लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्द्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।
- इस भवन में एक निश्चित अंतराल पर कट मार्क हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। विशेषज्ञों की नज़र में यह इंडो-सारसेनिक शैली का विस्तार है। विधानसभा का सदन का कार्यवाही हॉल अर्द्धगोलाकार शक्ल में है। विधानसभा परिसर में तीन हॉल, 12 कमरे हैं।
- वास्तुविद् ए.एम. मिलवुड ने बिहार विधानसभा भवन की डिज़ाइन तैयार की थी। इसकी आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। विधानसभा भवन के अगले हिस्से की लंबाई 230 फीट है। विधान मंडल के भवन को 1935 के अधिनियम के बाद दो हिस्सों में बाँटा गया। पहले हिस्से में विधानसभा और दूसरे में विधानपरिषद बनी।
- श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके मुख्यमंत्री काल में 18 सितंबर, 1947 को विधानसभा में ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ और 1950 में भूमि सुधार कानून पास हुआ।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद करीब दो साल तक बिहार के राज्यपाल रहे। इसके बाद वे राष्ट्रपति हुए। इनसे पहले जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल से राष्ट्रपति बने थे।

विपश्यना ध्यान

चर्चा में क्यों ?

- 21 अक्तूबर, 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'विपश्यना ध्यान' के लिये 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी।
- बुद्ध स्मति पार्क में करुणा स्तूप और बुद्ध स्मति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। इसे पहले मेडिटेशन केंद्र बनाया गया था, फिर बाद में इसे विपश्यना केंद्र बनाया गया।
- इस करुणा स्तूप में पाँच देशों- जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड से लाये गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इसके अलावा दलाई लामा द्वारा लाये गए बोधिवृक्ष भी यहाँ पर लगाये गए हैं।
- इस केंद्र में 10 दिनों का रहना-खाना बिल्कुल फ्री होता है। फिलहाल बिहार के पाँच जगहों पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इनमें पटना के अलावा बोधगया, मुज़फ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में भी सेंटर हैं।
- 'विपश्यना' ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है- चीज़ों को वैसे ही देखना, जैसे वो वास्तव में हैं। इसे ढाई हज़ार साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख है।
- गौरतलब है कि भगवान बुद्ध ने ध्यान की 'विपश्यना-साधना' से बुद्धत्व प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक विपश्यना भी है। विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देती है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देती है।

कृषि यंत्र बैंक

चर्चा में क्यों ?

- 23 अक्तूबर, 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 'रबी महाभियान' प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिये विभिन्न योजनाओं की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार, राज्य के 13 ज़िलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी।
- इन यंत्र बैंकों की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी ज़िलों में की जाएगी।
- यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी तथा इन समूहों के द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिये जाएंगे।
- कृषि यंत्र बैंकों के लिये सरकार 80 प्रतिशत अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है।
- इसके अतिरिक्त पटना एवं मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाने का प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं की शुरुआत इसी रबी मौसम में की जाएगी तथा तकनीकी ट्रेनिंग के लिये 40 हज़ार किसानों को एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा, जिसमें उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि के तहत चल रहीं विभिन्न योजनाओं को फील्ड में ले जाकर दिखाया जाएगा।

मनरेगा कार्यों में महिलाओं की 54 प्रतिशत हिस्सेदारी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक (लगभग 54 प्रतिशत) है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक राज्य में 10 करोड़ 23 लाख रोज़गार दिवस का सृजन हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 54 प्रतिशत रही है।
- वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के निबंधन से यह खुलासा हुआ है कि निबंधन कराने वाले 75 लाख कामगारों में भी आधे-से-अधिक महिलाएँ हैं।
- निबंधन कराने वालों में पुरुषों की भागीदारी मात्र 42.83 फीसदी है, वहीं महिलाओं की भागीदारी 57.17 फीसदी है।
- आँकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र से सबसे अधिक कामगारों ने निबंधन कराया है, जो कुल कामगारों का लगभग 50 फीसदी है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों का स्थान आता है, जिससे जुड़े लगभग 11 लाख कामगारों ने निबंधन कराया है।
- विदित हो कि बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है।

दृष्टि The Vision